

मुख्य समाचार :-

- प्रदेश में "स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार" अभियान के तहत अब तक चार लाख 39 हजार से अधिक लाभार्थियों ने विभिन्न शिविरों का लाभ उठाया।
- देहरादून में "आपदा के बाद आवश्यकता मूल्यांकन" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। विभिन्न विभागों के अधिकारी हुए शामिल।
- बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बदरीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
- उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने यमुनोत्री रोपवे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की।

स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार

प्रदेश में "स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार" अभियान बड़े पैमाने पर संचालित किया जा रहा है। 17 सितम्बर से शुरू हुआ यह अभियान आगामी दो अक्टूबर तक चलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में आयोजित इस महाअभियान ने कम समय में व्यापक उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। प्रदेशभर में 17 से 23 सितम्बर तक 9 हजार 112 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इनमें से 249 विशेषता शिविर रहे। 23 सितम्बर तक कुल चार लाख 39 हजार 973 लाभार्थियों ने इन शिविरों का लाभ उठाया। स्वास्थ्य शिविरों में विभिन्न बीमारियों की जांच और उपचार किया गया। इनमें स्वास्थ्य व रक्तदान शिविर, एनीमिया, क्षय रोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग, निःशुल्क दवा वितरण, पोषण और स्वच्छता पर परामर्श, महिलाओं व किशोरियों के लिए स्वास्थ्य एवं कौशल जागरूकता सत्र, नेतृत्व और संदेश अभियान, मुख्य गतिविधियाँ हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की माताओं और बहनों का स्वास्थ्य सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ महिला ही सशक्त परिवार और सशक्त समाज की आधारशिला है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को हर गांव और हर घर तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम

देहरादून स्थित उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में आपदा के बाद आवश्यकता मूल्यांकन- पीडीएनए विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। आपदा के बाद आवश्यकताओं का आकलन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए विभागों को दिशा-निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेषज्ञ अमित टंडन ने पीडीएनए की प्रक्रिया, इसके महत्व और कार्यान्वयन की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीडीएनए के तहत प्रभावित क्षेत्रों की क्षति का आकलन, पुनर्निर्माण की आवश्यकताएँ, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और दीर्घकालिक पुनर्वास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की जाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीडीएनए केवल एक तकनीकी प्रक्रिया न होकर, एक समग्र और सहभागी प्रक्रिया है, जिसमें सभी संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने पीडीएनए से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए, जिनका विशेषज्ञों ने समाधान करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पीडीएनए को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग व जिलों में पूरी तैयारी कर ली गई है।

स्वच्छता ही सेवा अभियान

स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगर पालिका परिषद चम्पावत कल एक विशेष वृहद स्वच्छता अभियान आयोजित करने जा रही है। यह कार्यक्रम "एक दिवस, एक घंटा, एक साथ" थीम पर आधारित होगा। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी भारत त्रिपाठी ने बताया कि यह अभियान सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चलेगा, जिसकी शुरुआत गांधी मूर्ति, मुख्य बाजार से होकर जीआईसी चौराहे तक की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह केवल सफाई का कार्यक्रम नहीं, बल्कि नागरिकों को स्वच्छता की जिम्मेदारी का बोध कराने का सामूहिक प्रयास है। नगर पालिका परिषद ने सभी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यापारिक संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं और आम नागरिकों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल सरकार या नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

तुंगनाथ

रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रल्हाद कोंडे ने चोपता से तुंगनाथ ट्रैक पर तुंगनाथ मन्दिर तक पैदल चलकर यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने तुंगनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनके यात्रा अनुभव जाने। श्री कोंडे ने प्रचलित यात्रा अवधि में जिले में स्थित धामों की पवित्रता सहित पैदल मार्ग की स्वच्छता बनाए रखने व इसकी मर्यादा भंग करने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई करने के थाना प्रभारी ऊखीमठ को निर्देश दिए। उन्होंने चौकी क्षेत्र के तहत निवासरत आम-जनमानस के साथ निरन्तर समन्वय गोष्ठी आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए।

बीकेटीसी

बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय प्रसाद थपलियाल ने बदरीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने श्री बदरीनाथ धाम दर्शन पंक्ति, पूजा काउंटर, भंडार कक्ष, कार्यालय, प्रसाद काउंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बदरीनाथ मंदिर परिसर में नवरात्रि पूजा पांडाल में मां दुर्गा, माता लक्ष्मी, देवी उर्वशी के दर्शन किये। श्री थपलियाल ने कहा कि बदरीनाथ और केदारनाथ यात्रा सुचारु रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान यात्रा सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से यात्रा में कुछ रुकावट आई थी, लेकिन अब सड़क मार्ग सुचारु होने से यात्रा ने गति पकड़ ली है। नवरात्र के दौरान तीर्थयात्रियों का दोनों धाम में निरन्तर आगमन हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक दोनों धाम में 29 लाख 36 हजार से अधिक तीर्थ यात्री दर्शनों को पहुंच चुके हैं।

यमुनोत्री रोपवे

उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने यमुनोत्री रोपवे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में परियोजना से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी और संबंधित निर्माण एजेंसी के अधिकारी वचुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान जिलाधिकारी ने यमुनोत्री रोपवे परियोजना की वर्तमान स्थिति, निर्माण कार्यों की प्रगति, पर्यावरणीय स्वीकृतियों, भू-अधिग्रहण की स्थिति और स्थानीय जनसहयोग की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रोपवे निर्माण में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने, समय-समय पर आवश्यक तकनीकी परीक्षण कराए जाने और पर्यावरण से जुड़े सभी पहलुओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि रोपवे का निर्माण, पर्यटन और यमुनोत्री यात्रा के लिए महत्वपूर्ण हैं, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारी, परियोजना के तहत चल रहे कार्यों का मौके पर स्थलीय निरीक्षण करें। साथ ही इससे जुड़े विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि रोपवे परियोजना को एक मॉडल के रूप में सफल बनाया जा सके।

जीएसटी

अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर— जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। अब लोग इस महीने की 22 तारीख से लागू जीएसटी सुधारों का लाभ उठा सकते हैं। नई कर संरचना के अंतर्गत जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की चार-स्तरीय संरचना से 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय संरचना में सरल बना दिया है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम करके, ये सुधार नागरिकों को काफी राहत दे रहे हैं। एक रिपोर्ट—